NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 26/NCRES/46/22 Date : 26.2.2022

श्रीमान अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली

महोदय,

प्रयागराज संगम की पावन धरती पर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रथम आगमन पर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) स्वागत एवं अभिनन्दन करता है, और आशा करता है कि आपके नेतृत्व में भारतीय रेल' निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा व कर्मचारियों की समस्यायों का भी उचित निदान सम्भव हो सकेगा।

NCRES को उम्मीद है कि कर्मचारी हित में निम्नलिखित विन्दुओं पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेगें।

1. NPS रद्द किया जाय।
2. रू. 43600/– से ऊपर वेतन पाने वालो को रात्रि भत्ते का भुगतान न किये जाने के कारण कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है। अतः इस सम्बन्ध में सभी कर्मचारियों को बिना किसी सीलिंग के रात्रि भत्ता देने हेतु शीघ्र आदेश जारी किया जाय।
3. SSE, GP-4600 के कैडर को GP- 4600 25%, GP- 4800 50%, एवं GP- 5400 25% के अनुपात में अपग्रेड किया जाय व टेक्नीशियन II को टेक्नीशियन I में मर्ज किया जाय।
4. Engg. (PWay), S&T, Electrical, OHE, C&W, TRD, Optg आदि सभी सेफ्टी कैटेगिरी के हेल्पर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजरों एवं आर्टीजन कैडर को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउन्स देने के सम्बन्ध में बोर्ड स्तर बनी कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय को तुरन्त लागू किया जाय।
5. रेलवे बोर्ड की योजना के अनुसार प्रयागराज स्टेशन के पुनर्विकास के लिये रेल कर्मचारियों की सबसे अच्छी रेलवे ट्रैफिक कालोनी के लगभग 300 रेल आवासो को तोड़े जाने से कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, इसलिये इस पर रोक लगाई जाय।

   भारत सरकार की "विरासत भी विकास भी" की कार्यपद्धति के तर्ज पर NCRES का सुझाव है कि प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड में भव्य चर्च (पत्थर गिरजा) से जंक्शन स्टेशन तक के वर्ष 1999 में बन्द किये गये यात्रियों के लिये सुविधाजनक सीधे मुख्य रास्ते को खोलते हुये सम्पूर्ण विकास ट्रैफिक कालोनी की तरफ न करके प्लेटफार्म 6 के सामने व DLI End की तरफ किया जाय जहाँ हजारो स्क्वायर मीटर जमीन खाली/परित्यक्त पड़ी है, ताकि स्टेशन का मध्य होने के कारण यात्रियों के लिये सुविधाजनक होने के साथ–साथ रेलवे राजस्व की बचत भी हो सके और कर्मचारियों को आवास भी खाली न करना पड़े।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री